राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

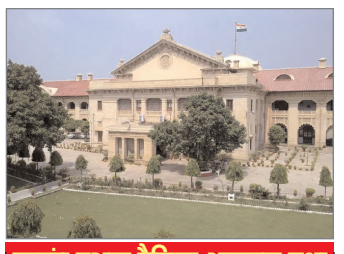

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, सोमवार, 29 जून 2026
वर्ष 14, अंक 81, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

संविधानयोगी सरकार के 'प्रोजेक्ट प्रवीण' से संवरेगा युवाओं का कल -मंत्री कपिल देव अग्रवाल ..03

फिर दहल रहा होर्मज; ईरान ने बहरीन पर दागीं मिसाइलें ,...04

इलाहाबाद हाई कोर्ट आदेश के खिलाफ सरकार करेगी अपील

● इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार करने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार आदेश के खिलाफ अपील करेगी। सरकार डबल बेंच या फुल बेंच में अपील दायर करेगी।

ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार करने का मामला

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार डबल बेंच या फुल बेंच में अपील करेगी। प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक को लेकर 13 जुलाई को फिर सुनवाई होगी, लेकिन प्रदेश सरकार इसके खिलाफ जोरदार तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनको योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रशासक बनाया। यह उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि प्रधानों को प्रशासक का चार्ज दिया गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इस याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक में पहले ही ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। यह आयोग प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आरक्षण तय होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव में करीब छह महीने की देरी हो सकती है। इसी को आधार बनाते हुए सरकार फैसले को चुनौती देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तारीख बताने को कहा है। इस बीच होने वाली अगली सुनवाई पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश भी सरकार को दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्राम प्रधानों को प्रशासक मानने से इनकार करने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार आदेश के खिलाफ अपील करेगी। सरकार डबल बेंच या फुल बेंच में अपील दायर करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने यह आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते। इसके साथ ही सरकार को चुनावी रुपरेखा पेश करने को कहा है। सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रुपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि सरकार ओबीसी समर्पित आयोग रिपोर्ट का तथ्य रख सकती है। सरकार का मानना है कि ओबीसी समर्पित आयोग के बिना नहीं हो सकते हैं।

कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म

यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था। प्रदेश में 57 हजार से ज्यादा ग्राम हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होने के चलते सरकार की तरफ से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया था। सरकार पहले ही ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। यह आयोग प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम पंचायतों में आरक्षण तय होगा। ऐसे में पंचायत चुनाव में करीब छह महीने की देरी हो सकती है।

यूपी पंचायत चुनाव में साढ़े 12 करोड़ से अधिक वोटर

राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे पहले हाल ही में पंचायत चुनाव से संबंधित वोटर लिस्ट भी जारी की थी। फाइनल की गई वोटर लिस्ट के मुताबिक, पंचाय चुनाव के लिए यूपी में अब 12 करोड़ 58 लाख से ज्यादा वोटर हैं। वोटर लिस्ट में लगभग 1.81 करोड़ से अधिक नए मतदाता जोड़े गए हैं।

दुष्कर्म पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए काफी: हाई कोर्ट

● इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म 'कानूनी शब्द' है और पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने 44 साल पुराने एक दुष्कर्म मामले में अभियुक्त राकेश की सात साल की सजा बरकरार रखी और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म 'कानूनी शब्द' है ना कि 'मेडिकल'। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए काफी है। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ दुष्कर्म के 44 साल पुराने मामले में अभियुक्त राकेश की आपराधिक अपील खारिज कर दी है और सात साल की सजा को बरकरार रखा है। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये जुर्माना और लगा दिया है। कहा है कि यह राशि एक महीने के भीतर पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए। अगर पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है तो अपीलार्थी राशि उसके कानूनी वारिसों को देगा। जुर्माना न देने पर छह महीने की और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सत्र न्यायालय ने मई 1983 में सजा सुनाई थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी के वकील का कहना है कि उसके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। पीड़िता और अभियोजन के अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं। अभियुक्त को इसलिए प्रोबेशन पर रिहा करना चाहिए क्योंकि मामला लगभग 42 वर्षों से कोर्ट में लंबित है और उसकी उम्र 60 साल से अधिक है। यह प्रकरण प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद) के कैंट थाने में दर्ज हुआ था। राजापुर निवासी नाबालिग पीड़िता ने अपनी गवाही में बताया था कि 22 फरवरी 1982 की सुबह करीब 9.30 बजे जब वह नाले के पास शौच के लिए गई थी तो मोहल्ले में ही रहने वाले अभियुक्त वहां मौजूद थे। सबसे पहले राकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर प्रकाश ने। विरोध करने पर उसे मारा-पीटा। पीठ ने गंगा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का उल्लेख भी किया कि दुष्कर्म पीड़िता के साक्ष्य को पुष्टि की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपीलार्थी के वकील की यह दलील भी भरोसेमंद नहीं मानी कि पीड़िता का चरित्र खराब था। कहा, प्रकरण में पीड़िता का बयान मेडिकल साक्ष्य से भी मेल खाता है, जिसमें शरीर पर छह चोटें दर्ज थीं। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को धारा 376 आइपीसी के तहत सही दोषी ठहराया है। हाई कोर्ट ने 23 जून को सुनाए गए अपने निर्णय में जमानत मुचलका तत्काल प्रभाव से रद करते हुए यह भी कहा है कि अगर अपीलार्थी जमानत पर है तो उसे बाकी बची सजा काटने के लिए 10 दिन के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में समर्पण करना होगा। ऐसा नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट तुरंत कानूनी कार्रवाई करे। अपीलार्थी को धारा 428 सीआरपीसी के तहत 'सेट-आफ' का लाभ मिलेगा। यानी मुकदमे के दौरान हिरासत में बिताई गई अवधि सजा में से घटाई जाएगी।

संक्षिप्त ख़बरें

पल्स पोलियो अभियान 28 जून से शुरू

सिद्धार्थनगर। उसका बाजार क्षेत्र में रविवार को 28 जून से पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जा रहा है। उसका बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉ. एसके पटेल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत से पोलियो (पोलियोमाइलाइटिस) का पूर्ण उन्मूलन करना है। अधीक्षक डॉ. एसके पटेल ने क्षेत्र के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए शून्य से लेकर पांच वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। उन्होंने कहा कि बूथ से छूटे हुए बच्चों को सोमवार से शुक्रवार घर -घर जाकर पोलियों की खुराक पिलाया जायेगा जिसके लिए छप्पन बूथ, सैंतीस टीम, चार ट्रांज़िट टीम, एक मोबाइल टीम और तेरह सुपरवाइजर बनाएं गए हैं जो कि कुल 23857 हजार बच्चों को खुराक देने का लक्ष्य रखा गया हैं।

श्रीकृष्ण जन्म की कथा सुन श्रोता हुए भाव विभोर

बिस्कोहर। ग्राम पंचायत खरिकवा केरवानिया में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के पांचवें दिन शुक्रवार की रात्रि कथा व्यास पंडित काली प्रसाद ने भगवान श्रीकृष्ण के अवतार की मार्मिक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जब-जब अधर्म बढ़ता है, तब-तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान श्रीकृष्ण जन्म प्रसंग के दौरान श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होकर भगवान श्रीकृष्ण जयघोष करते रहे। कथा के समापन पर आरती एवं प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान मंत्र राम यादव व गीता यादव सहित सौदागर, मुरली मौर्य, शिवदेव, जगराम, चंद्रप्रकाश विश्वकर्मा, चंद्रिका प्रसाद मिश्रा, दिवाकर प्रसाद मिश्रा, राजाराम यादव, धनीराम यादव, बृजलाल यादव, ओपी यादव, कुलदीप यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

01 जुलाई से लागू होगी विकसित भारत-जी राम जी योजना

● ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन के रोजगार का अवसर, आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण को मिलेगी नई गति

● उत्तर प्रदेश में योजना के शुभारंभ की जोरदार तैयारियां- केशव प्रसाद मौर्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी)' ग्रामीण भारत के विकास और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, उनकी आय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा तथा गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि 01 जुलाई, 2026 से लागू होने वाली इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के सशक्त संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार की गारंटी अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यह निर्णय ग्रामीण श्रमिकों की आय वृद्धि, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और गांवों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के अतिरिक्त दिनों से ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत होगी, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मौर्य ने कहा कि वीबी-जी राम जी अभियान ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, पारदर्शी प्रक्रिया और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। योजना के प्रभावी संचालन से गांवों में रोजगार के साथ-साथ विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गांवों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश के ग्रामीण परिवारों की भी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

सम्पर्क सूत्र-बी0एल0यादव

सहरिया बस्ती में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, गंभीर घायल

एससी-एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज

नाराहट में दबंगई का मामला, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी का भी आरोप

ललितपुर। थाना नाराहट क्षेत्र की सहरिया बस्ती में एक युवक के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के अनुसार गांव के एक युवक ने लाठी-डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरधा ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल ललितपुर रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ बीएनएस एवं एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना नाराहट निवासी लुखई पुत्र हरी अहिरवार द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया है कि 23 जून 2026 की शाम लगभग 8 बजे उनका पुत्र वकील गांव के राहुल यादव पुत्र भानसिंह यादव के साथ सहरिया बस्ती में मौजूद था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि राहुल यादव ने गाली-गलौज करते हुए वकील पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

लो वोल्टेज और ट्रिपिंग से ग्रामीण बेहाल

● गांव में एक और ट्रांसफार्मर लगाने की मांग

कौलापुर। भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली की लगातार ट्रिपिंग एवं लो वोल्टेज की समस्या से डीघ ब्लॉक के बेरासपुर गांव के ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। गांव में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं मिलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने विभाग से गांव में एक और 100 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आए दिन बिजली ट्रिप होने और लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। आरोप है कि कई बार ग्रामीण आपस में चंदा कर विद्युत कर्मियों से फाल्ट ठीक कराते हैं, लेकिन मरम्मत के बाद भी व्यवस्था एक-दो दिन से अधिक सुचारु नहीं रह पाती।

ग्रामीणों के अनुसार बेरासपुर में वर्तमान में 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है, जबकि गांव में बिजली की खपत लगातार बढ़ चुकी है। बढ़े हुए लोड के कारण ट्रांसफार्मर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे बार-बार फाल्ट और लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न होती रहती है। भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था चरमराने से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। उमस के कारण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है। विजय कुमार मिश्रा, बेचन मिश्रा, लक्ष्मीकांत तिवारी, भगेडू प्रजापति, चंद्रेश शर्मा, शिव प्रजापति, विनय शर्मा समेत ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से शीघ्र क्षमता वृद्धि करते हुए नया ट्रांसफार्मर स्थापित कराने की मांग की है, ताकि गांववासियों को निर्बाध और पर्याप्त बिजली आपूर्ति मिल सके।

क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई, फिर भी नहीं थम रहा अवैध खनन का खेल

उन्नाव। जिले के सोहरामऊ और अजगैन क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। बीती रात सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गोआमापुर और चिलौली गांव में कथित अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए सात डंपरों का चालान किया। इसके बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में खनन गतिविधियां जारी रहने के आरोप सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, माखी थाना क्षेत्र की ओर भी मिट्टी खनन जारी रहने की शिकायतें मिली हैं। वहीं सुबह थाना पुलिस ने बिना वैध रॉयल्टी के संचालन के संदेह में तीन डंपरों को रोककर जांच की। जांच के दौरान चालकों द्वारा प्रस्तुत रॉयल्टी पर्चियों की वैधता अवधि समाप्त पाई गई, जिसके बाद राजस्व चोरी और खनन नियमों के उल्लंघन की आशंका को लेकर मामला चर्चा का विषय बन गया।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के कारण सरकारी सड़कें, नहर की पटरी तथा चक मार्ग तेजी से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की भूमि और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पाली, माखी सहित कई इलाकों में लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध खनन से जुड़े मामलों में कुछ राजस्व कर्मियों की भूमिका पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। उनका कहना है कि खनन माफिया की गतिविधियों के चलते पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित विभागों द्वारा निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई आवश्यक होगी, ताकि राजस्व की चोरी पर रोक लग सके तथा पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रियल एस्टेट फ्रॉडः बिल्डर संदीप सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली-एनसीआर से कई अहम दस्तावेज किए जब्त

● ईडी ने कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में चार जगहों पर तलाशी ली

● ईडी का आरोप है कि बिल्डर संदीप सिंह ने 'सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति' के सदस्यों को वादा किए गए फ्लैट नहीं दिए और जमीन किसी और को बेचकर उनके साथ धोखाधड़ी की

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ईडी) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में 4 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई गाजियाबाद में जमीन और रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिल्डर संदीप सिंह और 'सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति' के पदाधिकारियों से जुड़ी जगहों पर की गई. ईडी ने यूपी पुलिस द्वारा दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. ये एफआईआर आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थीं, जो पीएमएलए, 2002 के तहत 'शेड्यूल्ड ऑफेंस' (निर्धारित अपराध) हैं एफआईआर के मुताबिक, संदीप सिंह (रूह्य श्रस्थ प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर) इस धोखाधड़ी के मुख्य लाभार्थी और मुख्य साजिशकर्ता थे. उन्होंने समिति के सदस्यों (जो सशस्त्र सीमा बल के रिटायर्ड अधिकारी हैं) को समिति की आधी जमीन पर 264 रिहायशी फ्लैट देने का वादा किया था, जिसके बदले में वो बाकी आधी जमीन बेचने या उसके डेवलपमेंट के अधिकार चाहते थे।

वादे के मुताबिक पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्ट

एफआईआप से यह भी पता चला कि

सदस्यों से तय समय में रिहायशी फ्लैट बनाने और देने या देरी होने पर हर महीने किराया देने का वादा किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट वादे के मुताबिक पूरा नहीं हुआ. इसके बजाय संदीप सिंह ने समझौते का गलत फायदा उठाया और सदस्यों के लिए फ्लैट पूरे किए बिना ही 41,544 वर्ग मीटर जमीन का आधा हिस्सा तीसरे पक्ष को बेच दिया. इस तरह उन्होंने गलत तरीके से फायदा उठाया और सदस्यों को उनके हक से वंचित कर दिया।

कई अहम दस्तावेज जब्त

ईडी इन निर्धारित अपराधों से हुई 'अपराध की कमाई' के बनने, छिपाने, कब्जे में रखने, हासिल करने और इस्तेमाल करने की जांच कर रही है. इसमें फंड का ट्रेल (लेन-देन का रास्ता) और उससे खरीदी गई संपत्तियां भी शामिल हैं. तलाशी के दौरान पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मनी ट्रेल, संपत्तियों और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आदि से जुड़े कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए. इससे पहले 25 जून को भी प्रवर्तन निदेशालय ने गाजियाबाद में कथित भूमि और रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन की जांच के तहत उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था।

सोनभद्र के ग्रामीण अंचलों में आर्थिक क्रांति की संवाहक बनतीं आत्मनिर्भर महिलाएं

उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं के परिणाम अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। प्रदेश सरकार की नीतियों और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समन्वय से सोनभद्र के सुदूर गांवों की महिलाओं के जीवन में एक अभूतपूर्व और सकारात्मक परिवर्तन आया है। पारंपरिक बंधनों और घर की चहारदीवारी से बाहर निकलकर महिलाएं अब लघु उद्योगों की स्थापना कर रही हैं और अपने परिवारों के आर्थिक संबल का मुख्य आधार बन रही हैं। यह बदलाव न केवल महिलाओं की व्यक्तिगत आय में वृद्धि कर रहा है बल्कि इस जनजातीय और ग्रामीण बहुल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति प्रदान कर रहा है। इसी विकास यात्रा की एक अद्वितीय मिसाल जनपद के विकास खंड करमा के ग्राम ककरही में देखने को मिलती है जहां महिलाओं ने सामूहिक प्रयास से आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिखी है।

सोनभद्र के ग्राम ककरही में संकल्प प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय संघ के तत्वावधान में स्थापित किया गया सोया मिल्क प्लांट ग्रामीण महिला उद्यमिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। इस प्लांट की स्थापना के बाद से क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़कर मौर्या आजीविका स्वयं सहायता समूह की अनेक महिलाएं वर्तमान में सोया मिल्क, सोया पनीर, सोया दही और सोया बड़ी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक उत्पादों का नियमित उत्पादन कर रही हैं। इन उत्पादों की बाजार में बढ़ती मांग के चलते समूह से जुड़ी प्रत्येक महिला हर महीने औसतन बीस हजार रुपये तक की सम्मानजनक आमदनी प्राप्त कर रही है जो जनपद के इस ग्रामीण परिवेश में उनके आर्थिक सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है।

त्योहारों और शादी-विवाह के विशेष अवसरों पर सोनभद्र के स्थानीय बाजारों में सोया पनीर की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है जिसके कारण महिलाओं के लिए इसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बड़ी और लाभप्रद चुनौती बन जाता है। इस व्यवसाय ने उन महिलाओं की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है जो पहले केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं और जिनके सामने अपने परिवारों के सुचारू भरण-पोषण की गंभीर समस्या बनी रहती थी। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और नियमित आय सुनिश्चित होने से इन महिलाओं का न केवल घरेलू स्तर पर सम्मान बढ़ा है बल्कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों के लिए भी वे पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। वैवाहिक सीजन के दौरान मांग में भारी उछाल आने से उनकी आय में और अधिक वृद्धि हो जाती है जिससे उनका उत्साह दोगुना हो जाता है।

इस सफल उद्यम की नींव को मजबूत करने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में संचालित इस मिशन के माध्यम से महिलाओं को सोयाबीन से दूध और पनीर बनाने की वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धतियों का गहन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। इस प्रशिक्षण सत्र ने महिलाओं को प्लांट के संचालन से लेकर उत्पादन की बारीक से बारीक तकनीकों को समझने में सक्षम बनाया। लगभग साढ़े तीन लाख रुपये की प्रारंभिक लागत से स्थापित इस सोया मिल्क प्लांट की दैनिक उत्पादन क्षमता इतनी सुदृढ़ है कि यहां हर दिन लगभग अस्सी किलोग्राम तक ताजा और शुद्ध सोया पनीर आसानी से तैयार कर लिया जाता है।

सोनभद्र और आसपास के स्थानीय बाजारों में इस शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक सोया पनीर की बढ़ती लोकप्रियता ने ग्रामीण महिलाओं के भीतर एक नया और सुदृढ़ आत्मविश्वास जगाया है। उत्पाद की निरंतर बिक्री और ग्राहकों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर इन महिलाओं ने अब अपने व्यापार का विस्तार करने की योजना बनाई है। स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य अब न केवल अपने मौजूदा सोया उत्पादों की व्यापक स्तर पर ब्रांडिंग और पैकेजिंग करने का विचार कर रही हैं बल्कि वे आने वाले समय में खोवा बनाने का एक नया आधुनिक प्लांट स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं। यह दूरदर्शिता दर्शाती है कि जनपद की ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ श्रमिक नहीं बल्कि कुशल व्यवसायी की भूमिका में आ चुकी हैं। इस उद्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इन महिलाओं ने केवल उत्पादन तक खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि उत्पाद की बिक्री के लिए स्वयं सक्रिय होकर बाजार भी विकसित किया है। उन्होंने सोनभद्र के विभिन्न होटलों, व्यावसायिक दुकानों, ढाबों और मैरिज लॉन व गेस्ट हाउसों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर अपने उत्पादों की व्यावसायिक आपूर्ति के रास्ते खोले हैं। महिलाओं के इस आत्मनिर्भर प्रयास और प्रशासनिक सहयोग के फलस्वरूप उन्हें राज्य स्तर पर गरिमामयी सम्मान भी प्राप्त हो चुका है जो उनके संघर्ष और सफलता की कहानी पर गौरव की मुहर लगाता है। यह सम्मान इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि ग्रामीण महिलाओं को उचित अवसर और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो वे समाज में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सकती हैं।

प्रदेश सरकार सोनभद्र सहित सभी ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी के उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की गति को तीव्र करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अत्यंत सुदृढ़ और प्रभावी संचालन कर रही है। राज्य के अत्यंत सुदूरवर्ती गांवों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने के उद्देश्य से क्रियान्वित इस मिशन के केंद्र में पूर्ण रूप से ग्रामीण महिलाएं ही हैं। इन महिलाओं को छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर किया जा रहा है। यह मिशन महज एक वित्तीय सहायता योजना नहीं है बल्कि इसने ग्रामीण समाज की सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच को बदलने और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का कार्य किया है।

उत्तर प्रदेश में इस मिशन के अंतर्गत लाखों महिलाओं को व्यवस्थित तरीके से संगठित करके उन्हें सीधे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। इस पारदर्शी व्यवस्था के कारण महिलाओं को बिना किसी मध्यस्थ या बिचौलिये के सीधे बैंक ऋण, अनुदान और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके खातों में मिल पा रहा है। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के इतिहास में यह मिशन एक युगांतरकारी कदम साबित हुआ है क्योंकि इसने महिलाओं को घर की चहारदीवारी के पारंपरिक परिवेश से बाहर निकालकर सीधे उद्यमशीलता की मुख्यधारा की ओर अग्रसर कर दिया है। मिशन के तहत गठित इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को कृषि, आधुनिक पशुपालन, डेयरी विकास, पारंपरिक हस्तशिल्प और सिलाई-कढ़ाई जैसे विविध क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस निरंतर तकनीकी सहायता और व्यावसायिक कौशल विकास से न केवल महिलाओं की कार्यक्षमता और हुनर में भारी वृद्धि हुई है बल्कि वे अपने स्थानीय स्तर पर ही छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों की सफलतापूर्वक स्थापना करने में सक्षम रही हैं। सोनभद्र जैसे विशिष्ट भौगोलिक परिवेश वाले जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ये कर्मठ महिलाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों का संचालन, परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल संकलन जैसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरे सरकारी कार्यों में भी अपनी सक्रिय और सराहनीय भागीदारी निभा रही हैं। इन विविध गतिविधियों से उनकी मासिक आय पूरी तरह सुनिश्चित हुई है जिससे ग्रामीण परिवारों के भरण-पोषण में उनकी स्थिति अत्यधिक मजबूत और निर्णायक हो गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक और सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि इसने ग्रामीण महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध किया है बल्कि उन्हें बेहतरीन वित्तीय साक्षरता भी प्रदान की है। डिजिटल लेन-देन और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के प्रति जागरूक बनाकर महिलाओं को समाज में एक नया दृष्टिकोण दिया गया है। मिशन के अंतर्गत शुरू की गई 'बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी' यानी बीसी सखी जैसी अभिनव और दूरदर्शी पहलों ने ग्रामीण अंचलों में वित्तीय सेवाओं को घर घर के दरवाजे तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया है। इस व्यवस्था ने जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग को सुगम बनाया है वहीं दूसरी ओर सैकड़ों महिलाओं के लिए नियमित रोजगार और सम्मान के नए द्वार पूरी तरह खोल दिए हैं। डिजिटल और वित्तीय साक्षरता से लैस होकर ग्रामीण महिलाएं अब स्वयं अपनी बचत और निवेश से जुड़े वित्तीय फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम हो चुकी हैं जिससे उनके आत्मसम्मान को एक नया आकाश मिला है। जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार सोया पनीर और अन्य स्थानीय उत्पादों की व्यापक स्तर पर ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को हर संभव तकनीकी व प्रबंधकीय मदद उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं ताकि इन ग्रामीण उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। सामूहिक सहभागिता, सरकारी नीतियों के ईमानदार क्रियान्वयन और महिलाओं के अटूट हौसलों के संगम से सोनभद्र का ग्रामीण अंचल आज पारंपरिक बंधनों को तोड़कर एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रहा है जहां नारी शक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह सशक्त होकर विकसित समाज के निर्माण का सबसे मजबूत और अटूट आधार बन चुकी है। **जनपद सोनभद्र**

उ.प्र. में भाजपा का नया संगठनः 'मिशन 2027' की तैयारी तेज

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश भाजपा में सबसे बड़ा संगठनात्मक बदलाव दस्तक दे रहा है। दिसंबर 2025 में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब पार्टी 'टीम यूपी 2.0' को अंतिम रूप देने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव सिर्फ फेरबदल नहीं, बल्कि 2027 की 'वार रूम टीम' है। 50% तक नए चेहरे को तबज्जों दी गई हैं और यह'एंटी-इंकबेंसी' काटने की तैयारी है। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि नई टीम में करीब 50% बदलाव होंगे। इसका मकसद है- नए चेहरे, नया जोशः लंबे समय से एक ही पद पर जमे लोगों को हटाकर युवा और बूथ लेवल तक पकड़ रखने वालों को मौका। दोहरी जिम्मेदारी खत्मः कई पदाधिकारियों के पास संगठन + सरकार दोनों का चार्ज है। अब इसे खत्म किया जाएगा। 2024 का सबकः लोकसभा चुनाव में यूपी में सीटें घटने के बाद पार्टी अब PDA के जवाब में OBC- युवा आउटरीच पर फोकस कर रही है। सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले यूपी को भाजपा ने 6 क्षेत्रों में बांटा हैः काशी, अवध, गोरखपुर, कानपुर, ब्रज, बुंदेलखंड। भाजपा ने सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया है । नए अध्यक्ष अपनी टीम खुद बनाएंगे। जाति-क्षेत्र का फॉर्मूलाः पश्चिमः गुर्जर-वैश्य को तवज्जो, अवधः ब्राह्मण नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति। ब्रज में शाक्य या लोध समाज से बड़ा चेहरा। काशी में OBC, खासकर पटेल/कुर्मी प्रतिनिधित्व। प्रदेश कार्यकारिणी में बड़ा कट- वर्तमान में प्रदेश टीम में 7 महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष, 16 सचिव हैं। क्या बदलेगाः महामंत्री 7 से 6 होंगे। यूपी की विशालता को देखते हुए ढांचा तो वही रहेगा, लेकिन पद कम होंगे। युवा + महिलाः टीम में एक तिहाई महिलाओं को प्रतिनिधित्व। उम्र पर खास ध्यान। 7 मोर्चों के नए अध्यक्षः युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान, ओबीसी, SC, ST, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी जल्द घोषित होंगे। 'मंत्रिमंडल के बाद संगठन' मॉडल- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में कैबिनेट विस्तार किया। अब उसी तर्ज पर संगठन में बदलाव हो रहा है। संतुलन का खेलः जिन क्षेत्रों से मंत्री ज्यादा हैं, वहां संगठन में पद कम होंगे ताकि असंतुलन न रहे। ब्रजः 12 मंत्री हैं, इसलिए संगठन में भागीदारी कम हो सकती है गोरखपुरः कैबिनेट में विस्तार नहीं मिला, तो प्रदेश इकाई में ज्यादा चेहरे मिल सकते हैं। PDA vs भाजपा का नया फॉर्मूला। 2027 चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति 3 पिलर पर है। PDA का मुकाबला*: गैर-यादव OBC जैसे कुर्मी, लोध, मौर्य, सैनी, निषाद, राजभर को अहम जिम्मेदारी। पंकज चौधरी का कुर्मी बैकग्राउंड पूर्वांचल में OBC वोट साधेगा। बूथ मजबूतीः सोशल मीडिया + जमीनी अभियान में सक्रिय, बूथ तक पकड़ वाले चेहरे। क्षेत्रीय संतुलनः पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज को ज्यादा प्रतिनिधित्व। ये सिर्फ संगठन नहीं, बल्कि भाजपा का '2027 मॉडल' है। लक्ष्य साफ है - नए चेहरों, सामाजिक समीकरण और बूथ मैनेजमेंट के जरिए सपा के PDA को काटकर फिर से 2/3 बहुमत लाना। अब देखना ये है कि 'परफॉर्मेंस' जीतता है या 'पैरवी'।

आगजनी के हादसों में कब तक झुलसती रहेंगी मासूम जिंदगियां?

विज्ञान ने मानव जीवन को जितनी सुविधाएं प्रदान की हैं, उतनी ही चुनौतियां भी खड़ी की हैं। आधुनिक तकनीक और विकास के इस दौर में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह विडंबना ही है कि विज्ञान का वरदान कई बार मानवीय लापरवाही और स्वार्थ के कारण अभिशाप में बदल जाता है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश होने के कारण भारत में आगजनी की घटनाओं से जन-धन की हानि का जोखिम भी सबसे अधिक है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अधिकांश हादसे प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही, नियमों की अनदेखी, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के कारण होते हैं। इन दुर्घटनाओं की कीमत अक्सर निर्दोष और मासूम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। भारतीय संविधान और भवन निर्माण संबंधी नियमों के अंतर्गत प्रत्येक शहर और गाँव में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। इन नियमों का पालन कराना स्थानीय निकायों और प्रशासन की जिम्मेदारी है। किंतु आज विकास की अंधी दौड़ में ऊँची-ऊँची इमारतें तो खड़ी हो रही हैं, पर उनमें रहने और काम करने वालों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। यदि ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और महानगर पालिकाओं द्वारा निष्पक्षता और ईमानदारी से निरीक्षण कराया जाए, तो देश के अधिकांश शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे भवन मिलेंगे, जिनका निर्माण नियमों की अनदेखी कर किया गया है। कहीं अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, तो कहीं आपातकालीन निकास तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे भवन किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। देश के अधिकांश शहरों, कस्बों और जिला मुख्यालयों के बाजार लगातार संकरे होते जा रहे हैं। अतिक्रमण और अवैध निर्माण ने चौड़ी सड़कों को भी संकीर्ण गलियों में बदल दिया है। प्रभावशाली लोगों के दबाव और भ्रष्ट तंत्र के कारण प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप जब आग लगती है, तब दमकल की गाड़ियां घटनास्थल तक पहुँचने में भी असमर्थ हो जाती हैं और छोटी-सी घटना कुछ ही मिनटों में भीषण त्रासदी का रूप ले लेती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई भीषण आग की घटना ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर दिया। यह हादसा केवल एक शहर की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। प्रश्न यह है कि आखिर आधुनिकता और विकास की इस अंधी दौड़ में कब तक मासूम जिंदगियां यूँ ही आग की लपटों में समाती रहेंगी? आज सरकारी अभिलेखों में सड़कों की चौड़ाई कुछ और है, जबकि वास्तविकता कुछ और। धीरे-धीरे अतिक्रमण और अवैध निर्माण ने सार्वजनिक स्थानों को निगल लिया है। विकास के नाम पर नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और धनबल तथा प्रभाव के सहारे अवैध निर्माण को वैधता का संरक्षण मिलता दिखाई देता है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती, तब तक सब कुछ सामान्य माना जाता है। लेकिन जैसे ही कोई भीषण हादसा होता है, तब प्रशासन को अचानक अवैध निर्माण, अग्नि सुरक्षा की कमी और नियमों के उल्लंघन याद आने लगते हैं। यदि यही सतर्कता पहले दिखाई जाए, तो अनेक जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति केवल ऊँची इमारतों और आधुनिक तकनीक से नहीं होती, बल्कि कानून के प्रति सम्मान, ईमानदारी और नागरिक जिम्मेदारी से होती है। भ्रष्टाचार केवल सरकारी तंत्र की समस्या नहीं है, बल्कि वह नागरिकों की गलत मानसिकता का भी परिणाम है। जब लोग नियमों का पालन करने के बजाय शॉर्टकट अपनाने लगते हैं, तब दुर्घटनाएँ अनिवार्य हो जाती हैं। आगजनी, जलभराव और अवैध निर्माण से होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, यदि सरकार कठोर इच्छाशक्ति का परिचय दे। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी प्रत्येक घटना में संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका तथा जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए। जब तक लापरवाही पर कठोर दंड नहीं मिलेगा, तब तक व्यवस्थाएँ नहीं सुधरेंगी। दुर्भाग्य यह भी है कि हर बड़े हादसे के बाद पूरा देश कुछ दिनों तक शोक व्यक्त करता है, संवेदनाएँ प्रकट करता है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के बड़े-बड़े संकल्प लिए जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ भुला दिया जाता है और व्यवस्था फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। अगली त्रासदी तक हमारा यह क्षणिक वैराग्य समाप्त हो जाता है। यदि वास्तव में निर्दोष नागरिकों का जीवन बचाना है, तो सरकार, प्रशासन और समाज—तीनों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से निभानी होंगी।

अरविंद रावल

वन्यजीव नहीं, उजड़ते जंगल गांवों के दरवाज़े पर हैं

[गांवों पर बढ़ता वन्यजीव संकट, विकास नीति पर उठते सवाल]

[सिकुड़ते जंगल, बढ़ता भय — विकास की कीमत कौन चुकाएगा?]

जंगलों से उठती आह अब गांवों की दहलीज तक सुनाई देने लगी है। आधी रात खेतों में उतरते हाथी, बस्तियों के आसपास मंडराते तेंदुए और घरों की चौखट तक पहुंचते बाघ केवल वन्यजीव नहीं, बल्कि उस अंधाधुंध विकास के मौन साक्ष्य हैं जिसने उनसे उनका आशियाना छीन लिया। विडंबना यह है कि जिस देश ने सदियों तक वृक्षों को देवता और वन्यजीवों को प्रकृति का परिवार माना, वहीं आज गांवों में जंगल का नाम भय का पर्याय बनता जा रहा है। यह संघर्ष किसी एक किसान और एक जानवर के बीच नहीं, बल्कि उस बिगड़े संतुलन की कहानी है जिसमें मनुष्य ने प्रकृति की सीमाएं लांघ दीं और अब प्रकृति उसी भाषा में जवाब दे रही है। सवाल यह नहीं कि वन्यजीव गांवों में क्यों आ रहे हैं, असली सवाल यह है कि उनके जंगल आखिर बचे कहां हैं? आंकड़े बताते हैं कि यह संकट अब भयावह हकीकत बन चुका है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच हाथियों के हमलों में 2700 से अधिक लोगों की जान गई, यानी हर साल करीब पांच सौ परिवार उजड़ रहे हैं। बाघों और तेंदुओं के हमले भी लगातार बढ़ रहे हैं। खेतों की तबाही ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। महाराष्ट्र में वन्यजीवों से कृषि नुकसान प्रतिवर्ष दस हजार से चालीस हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। कर्नाटक के कोडागु में आधे किसान हर साल करीब नब्बे हजार रुपये गंवा रहे हैं। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के कई क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक किसान वन्यजीवों को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, क्योंकि उनकी आधे से अधिक फसल जंगल निगल जाता है। जलवायु परिवर्तन, सिकुड़ते जंगल और बेलगाम विकास ने ऐसी स्थिति बना दी है कि न जंगल सुरक्षित हैं, न गांव। मध्यप्रदेश का बावनगजा भी इस बढ़ते संकट की आहट महसूस कर रहा है। दुनिया यहां 52 गज ऊंची जैन प्रतिमा देखने आती है, लेकिन स्थानीय लोग वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही का असर भी देख रहे हैं। भीषण गर्मी से जंगलों के जलस्रोत सूख गए, भोजन घटा और वन्यजीव गांवों की ओर उतर आए। दिन में श्रद्धालुओं की घंटियां गूंजती हैं, रात में जंगल की हलचल बढ़ जाती है। कई बार खेतों को नुकसान पहुंचता है और ग्रामीणों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। बावनगजा आज केवल तीर्थ नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय संकट का प्रतीक बन चुका है, जहां प्रकृति और विकास आमने-सामने खड़े हैं। यह संकट अब खेतों से निकलकर पूरे ग्रामीण जीवन पर छा चुका है। बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते बदलते हैं। महिलाएं जंगल की ओर कदम बढ़ाने से पहले कई बार सोचती हैं। बुजुर्ग रातभर घर और खेत की रखवाली करते हैं। भय अब दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। उधर मुआवजे की जटिल प्रक्रिया पीड़ित परिवारों की पीड़ा और बढ़ा देती है। सरकारी फाइलें उस किसान का दर्द नहीं समझती, जिसकी फसल, मवेशी या अपना एक पल में छिन गया। नतीजा यह है कि जिस समाज ने कभी वन्यजीवों को पूजनीय माना था, वही आज उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा है। सह-अस्तित्व की भारतीय परंपरा अब अविश्वास में बदलती जा रही है। इस संकट का हल केवल बंदूक, पिंजरे या वन्यजीवों को खदेड़ने में नहीं है। रास्ता वहीं निकलेगा, जहां विज्ञान, संवेदना और प्रभावी नीति साथ चलें। जंगलों के प्राकृतिक कॉरिडोर सुरक्षित हों, सौर फेंसिंग और सुरक्षा खाइयां बनें, रियल-टाइम ट्रैकिंग प्रणाली विकसित हो तथा गांवों तक त्वरित चेतावनी पहुंचे।

सबसे जरूरी है कि नुकसान का मुआवजा पारदर्शी और समयबद्ध मिले, ताकि किसान को न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। यदि विकास परियोजनाओं पर हजारों करोड़ खर्च हो सकते हैं, तो जंगलों की सीमा पर देश की पहली चौकी बने लोगों की सुरक्षा और सम्मान भी उतनी ही प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। बावनगजा जैसे क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती। सामुदायिक गश्त, वन विभाग और ग्रामीणों के बीच सतत संवाद, वैज्ञानिक इको-टूरिज्म तथा हर्बल खेती, वन-उत्पाद आधारित उद्योग और पर्यटन से जुड़ी आजीविकाएं इस संकट को अवसर में बदल सकती हैं। जब गांव की आजीविका जंगल से जुड़ेगी, तब जंगल दुश्मन नहीं, सहयोगी बनेगा। बच्चों की शिक्षा में भी वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व को केवल पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन-दृष्टि बनाना होगा। आखिर संरक्षण कानूनों से नहीं, संस्कारों से मजबूत होता है। सबसे बड़ा सवाल हमारी विकास नीति के सामने खड़ा है। क्या विकास का अर्थ केवल जंगल काटकर सड़कें बिछाना है? क्या प्रगति का पैमाना सिर्फ कंक्रीट का विस्तार है? यदि यही सोच रही, तो आने वाले वर्षों में गांवों और जंगलों का संघर्ष और भयावह होगा। प्रकृति प्रतिशोध नहीं लेती, वह केवल अपना संतुलन वापस मांगती है। जब मनुष्य उसकी सीमाएं लांघता है, तब प्रकृति उसे उसकी अपनी सीमाओं का अहसास करा देती है। इसलिए विकास को प्रकृति-विरोधी नहीं, बल्कि प्रकृति-संगत बनाना अब विकल्प नहीं, राष्ट्रीय आवश्यकता है। देश के वन-सीमांत गांव एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। बावनगजा से लेकर कोडागु और पश्चिमी घाट तक एक ही पुकार है—जंगल बचेंगे तो गांव बचेंगे, गांव बचेंगे तो किसान बचेगा और किसान बचेगा तो भारत बचेगा। मनुष्य और वन्यजीवों का यह संघर्ष किसी एक की जीत से नहीं थमेगा। इसका समाधान केवल संतुलन, सह-अस्तित्व और इस स्वीकार में है कि धरती पर जितना अधिकार मनुष्य का है, उतना ही जंगल के हर जीव का भी। इतिहास बताता है कि जिसने प्रकृति को चुनौती दी, अंततः वही पराजित हुआ। अब फैसला हमारे हाथ में है—चेतावनी को समझें या आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल पछतावा छोड़ जाएं।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

दैनिक राशिफल

मेषः आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा तथा आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा।

वृषभः कारोबार और नौकरी में प्रगति के संकेत हैं। पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात हो सकती है, जिससे भविष्य में लाभ के अवसर बनेंगे।

मिथुनः रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

कर्कः परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप सफलता से पूरा करेंगे।

सिंहः आत्मविश्वास के बल पर महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें।

कन्याः व्यापार में लाभ के अच्छे योग हैं। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखने से दिन बेहतर रहेगा।

तुलाः सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे और रुके हुए कार्यों में गति आएगी।

वृश्चिकः आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा।

धनुः करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मकरः कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

कुंभः नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

मीनः भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी तथा मन शांत रहेगा।

प्राकृतिक आपदा आने से पहले तैयार रहना होगा, आपदा पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक

आपदा सदैव अनअपेक्षित घटना होती है। जो मानवीय नियंत्रण से सदैव से बाहर होती है। प्राकृतिक आपदा अल्प समय में बिना किसी पूर्व सूचना के घटित होती है, जिससे मानव जीवन के सारे क्रियाकलाप अवरुद्ध हो कर,जान और माल की बड़ी हानि होती है । आर्थिक तंत्र एवं विकास तीतर बितर हो जाते हैं। आपदा की विद्रूपता, भयानक स्वरूप एवं निरंतरता मानव जीवन तथा समाज, देश को बड़ी हानि पहुंचाते हैं, एवं उस देश की आर्थिक स्थिति में गहरी चोट करते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से देश की प्रगति.पर चोट पहुंचती है। तथा राष्ट्र को आर्थिक रूप से बहुत पीछे खींच कर ले जाती है। आपदा प्रबंधन में जापान से सीख ली जा सकती है। क्योंकि जापान आपदा प्रबंधन में विश्व में अग्रणी देश माना जाता है। जापान पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र में अवस्थित है, जहां भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं सदैव आती रहती हैं। जापान में आपदा प्रबंधन की अत्याधुनिक तकनीक को याकोहामा रणनीति कहा जाता है। जापान में आपदा प्रबंधन की साल भर नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर एक्सरसाइज की जाती रहती है, एवं आपदाओं पर निरंतर निगरानी तथा नजर रखी जाती है,एवं इसके निदान के लिए पूर्व से ही सुनियोजित योजना बनाकर नागरिकों को सुरक्षित कर लिया जाता है। भारत को भी इसी तरह आपदा प्रबंधन को अपनाकर अन्य आपदाओं के साथ कोविड-19 के लिए सतर्क होकर कार्रवाई की जानी चाहिए। आपदाओं के प्रति मानवीय सभ्यता के संदर्भ में समाज के आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को ज्यादा प्रभावित करती है। एवं समाज का सबसे संवेदनशील तबका यानी वृद्ध व्यक्ति, महिलाएं, बच्चों, दिव्यांग लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। आपदा के समय सबसे ज्यादा निम्न आय वर्ग का व्यक्ति तथा मजदूर तबके का व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होकर उसकी दिनचर्या समूह रूप से छिन्न-भिन्न हो जाती है, एवं आर्थिक साधन भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे आजीविका का एक बड़ा भय सताने लगता है। भारत के भू भाग का लगभग 58% क्षेत्र भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है, जिसमें हिमालयिन क्षेत्र,पूर्वोत्तर राज्य, गुजरात का कुछ क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूकंप की दृष्टि से सबसे सक्रीय क्षेत्र रहें है। देश के 65 से 68% भूभाग पर कभी कम कभी ज्यादा भीषण रूप से सूखा पड़ता है, इसी तरह भारत के पश्चिमी और प्रायद्वीपीय राज्य में मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध शुष्क न्यून नमी वाले क्षेत्र सूखे से सदैव प्रभावित रहते हैं। बाढ़ से प्रभावित भूमि का विस्तार क्षेत्र देश के 12% है, यानी 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन में भूकंप आने की संभावना सदैव बनी रहती है। हिमालय क्षेत्र देश के पर्वतीय क्षेत्र मैं भूस्खलन की गंभीर समस्या की संभावना सदैव बनी रहती है। देश के विशाल तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात तथा सुनामी की भयावह स्थिति की संभावना सदैव बनी रहती है।अब भारत में विश्व के साथ-साथ करोना संक्रमण की भयानक महामारी से प्रभावित होकर हजारों लाखों नागरिकों की जान गवा कर इस आपदा से जंग लड़ रहा है, यह कोविड-19 की महामारी या आपदा प्राकृतिक है या मानव निर्मित यह तो भविष्य ही बताएगा, किंतु इस महामारी ने पूरे वैश्विक स्तर पर आकस्मिक रूप से मानव जीवन में मृत्यु का तांडव मचा के रख दिया है। ऐसी ही अनपेक्षित आपदाओं का पूर्वानुमान अथवा आकलन किया जाना पहले से संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय अन्य योजनाओं के साथ-साथ आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अत्यधिक सावधानी पूर्वक योजना तथा विभाग बनाने चाहिए, देश में जापान जैसे देश की तरह आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन सिस्टम को तैनात कर तैयार रखने की आवश्यकता होगी। भारत को आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग को चुस्त-दुरुस्त तथा अत्याधुनिक तकनीक से युक्त रखने की आवश्यकता है। तूफानी चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप, सूखा बाढ़ के अलावा अब कोविड-19 यानी करोना संक्रमण जैसी खतरनाक बीमारियां भारत देश को अपना निशाना बना कर रखा है ।ऐसे में भारत में मध्यम दर्जे का या निम्न दर्जे का आपदा प्रबंधन सिस्टम किसी भी काम का ना रहेगा, एवं इससे भारी जानमाल की हानि होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए 1990 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट सेल स्थापित किया गया था। लेकिन 1993 में लातूर के भूकंप तथा 1998 में मालपा के भूस्खलन तथा 1999 में ओडिशा में सुपर साइक्लोन तथा 2001 में भुज के भूकंप के बाद देश में एक मजबूत आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की जरूरत को महसूस करते हुए जे,सी, पंत जी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में एक सुव्यवस्थित तथा व्यापक सिस्टम तथा विभाग की स्थापना की आवश्यकता प्रतिवेदित की गई थी। 2002 में आपदा को देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला मानते हुए आपदा को गृह मंत्रालय के अंतर्गत समाविष्ट किया गया। आपदा प्रबंधन के इतिहास में 2005 में एक बड़ा परिवर्तन लाया गया भारत सरकार ने आपदा को अपनी कार्ययोजना के एक चक्रीय क्रम के रूप में प्रबंधित किया, जिसमें आपदा आ जाने के बाद इसके बचाव, नुकसान की भरपाई, निदान तथा आपदा आने के पूर्व की तैयारी तथा योजना को मूर्त रूप देने का एक सुनियोजित तरीका तैयार किया गया था। आपदा से खतरे का स्तर सभी इंसानों के लिए सदैव एक जैसा होता है। किंतु समाज के विभिन्न वर्गों में खतरे से निपटने तथा जूझने की क्षमता अलग-अलग होती है। निम्न वर्ग का तबका अन्य लोगों की अपेक्षा आपदा से ज्यादा प्रभावित होता है। अतः सरकार को गरीब तथा वंचित वर्ग के तबके के लिए आपदा प्रबंधन में विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। आपदाओं के प्रबंधन एवं अनुसंधान व त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तथा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन किया गया है। यह आपदा राशि कार्रवाई बल पर किसी खतरनाक आपदा की स्थिति में रासायनिक, जैविक, परमाणु विकिरण तथा अन्य प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा के संबंध में विशिष्ट कार्यवाही के निर्वहन का उत्तरदायित्व है। ईस संस्था ने बंगाल तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में आई सुनामी में काफी बड़ी संख्या में लोगों की जान भी बचाई है। चक्रवाती तूफान से निपटने में हमारे समुचित प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। परंतु पिछले 1 वर्षों से करोना संक्रमण से हुई बड़ी संख्या में मृत्यु ने देश को हिला कर रख दिया है। और कोविड-19 की प्रथम लहर के बाद द्वितीय लहर ने मृत्यु का तांडव मचा कर देश में हाहाकार मचा दिया है ।

कोविड-19 की पहली लहर के बाद एवं दूसरी लहर के मध्य देश के आपदा प्रबंधन सिस्टम को पहले से ही सावधान तथा सचेत रहकर पूरी की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी ।अगर आपदा प्रबंधन सिस्टम को लगातार मॉनिटर किया जाता एवं उस सिस्टम के अधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति सचेत एवं सजग रहते, तो द्वितीय लहर में इस तरह हड़कंप संक्रमण एवं मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। भारत को आपदा प्रबंधन के सिस्टम पर फिर से आंकलन कर एक नई व्यूह रचना बनाकर गरीब तबके निचले व्यक्ति तथा समग्र रूप से मानव जाति की सुरक्षा के लिए नए-नए उपाय करने चाहिए। क्योंकि आपदा कभी बताकर नहीं आती।इसी तरह कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी तैयारी पूर्व से ही कर लेना चाहिए अन्यथा हाथ मलने के अलावा अपने पास कुछ ना रह जाएगा।

संजीव ठाकुर

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

अग्निकांड के बाद फायर विभाग ने लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थानों का किया निरीक्षण

लालगंज (रायबरेली)। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग सतर्क हो गया है। शनिवार को अग्निशमन केंद्र के प्रभारी मुकेश गिरी के नेतृत्व में टीम ने नगर की लाइब्रेरी और शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई। टीम ने संज्ञान लाइब्रेरी, गुरुकुल कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य संस्थानों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने भवनों में उपलब्ध अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संचालकों को आग लगने की स्थिति में बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही फायर सेफ्टी के सभी नियमों का पालन करने और सुरक्षा उपकरणों को हमेशा क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए। अग्निशमन प्रभारी मुकेश गिरी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संस्थानों को फायर सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।

होटल में कारीगर का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, मचा हड़कंप

लालगंज, रायबरेली। कस्बे के निराला नगर स्थित एक होटल में शनिवार सुबह कारीगर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान आचार्य नगर निवासी मिथुन उर्फ अजय प्रजापति (30) पुत्र सत्यदेव के रूप में हुई है। अजय पिछले करीब नौ वर्षों से होटल में खाना बनाने का काम कर रहा था। शनिवार सुबह वह होटल के अंदर अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद होटल कर्मचारियों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों में चर्चा है कि अजय मोबाइल चार्जिंग के दौरान करंट की चपेट में आया, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। अजय चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसके परिवार में भाई श्रीकृष्ण, छोटेलाल, विनोद, पत्नी रूबी और सात वर्षीय बेटा वीरांश हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की

यूपी में अगले 6 महीनों में 15 लाख घरों तक पहुंचेगी PNG

लखनऊ। प्रदेश में एलपीजी (लाइट पेट्रोलियम गैस) पर निर्भरता घटाने के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास रही है। वर्ष के बचे हुए छह माह में सरकार 15 लाख घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचायेगी। दक्षिण-पश्चिम एशिया में युद्ध से उपजे एलपीजी संकट से सबक लेकर सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया था। जिसके बाद तेजी से कनेक्शन दिये गये। 24 जून तक 1.60 लाख से अधिक घरों तक कनेक्शन पहुंच गया। सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 16,23,163 कनेक्शनों के लक्ष्य के मुकाबले 9.86 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है। यानी बचे हुए छह माह में 15 लाख घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य है।

योगी सरकार के 'प्रोजेक्ट प्रवीण' से संवरेगा युवाओं का कल -मंत्री कपिल देव अग्रवाल

●वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 36,103 युवाओं का प्रशिक्षण लक्ष्य जारी

15 जुलाई 2026 से शुरू होंगी कक्षाएं, बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थी

आईटी, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर समेत प्रमुख सेक्टर्स में मिलेगा प्रशिक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ रोजगारपरक कौशल से जोड़ने की मुहिम तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के अन्तर्गत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार का मुख्य ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी युवा हुनर से वंचित न रहे। 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के जरिए हम राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में मजबूत कर रहे हैं। इस योजना के तहत आईटी (आईटी-आईटीईएस), हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल, ब्यूटी एंड वेलनेस और कृषि जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रत्येक बैच में अधिकतम 35 प्रशिक्षणार्थियों की सीमा तय की गई है। इससे बच्चों को प्रयोगात्मक और व्यावहारिक ज्ञान बेहतर ढंग से मिल सकेगा। इस वर्ष प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रदेश भर में कुल 36,103 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे आगरा, बरेली, आजमगढ़, ललितपुर, वाराणसी, रामपुर, शाहजहांपुर, जालौन और सोनभद्र सहित राज्य के राजकीय विद्यालयों में सूची बद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपीएस) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सेक्टर्स में आईटी-आईटीईएस, हेल्थकेयर, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, मैनेजमेंट, ग्रीन जॉब्स और एग्रीकल्चर शामिल हैं। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 300 घंटे होगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को सख्त समय-सीमा का पालन करना होगा। प्रशिक्षण प्रदाताओं को केंद्र की स्थापना, पंजीकरण और बैच निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर 15 जुलाई, 2026 तक हर हाल में कक्षाओं का संचालन शुरू करना होगा। बैच शुरू होने के 07 कार्य दिवसों के भीतर सभी छात्र-छात्राओं को पाठ्य सामग्री का वितरण कर उसकी तस्वीरें मिशन पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। यदि कोई प्रशिक्षण प्रदाता समय पर कार्य आरंभ नहीं करता है या जनपद स्तर से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त विधिक कार्यवाही की जाएगी।

सम्पर्क सूत्र-धर्मवीर खरे

परिवहन मंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग 01 जुलाई से बसों के खिलाफ चलाएगा विशेष जांच अभियान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग 01 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान का लक्ष्य न केवल नियम लागू करना है, बल्कि स्कूल परिवहन को एक सुरक्षित जवाबदेह और पारदर्शी सेवा बनाना है। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस, सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन, जांच इत्यादि की जाएगी। जांच में बस बॉडी की संरचना, बस की छत की निर्धारित भार मानक के अनुसार मजबूती, सीट एवं सीट एंकरेज टेस्ट, बॉडी चेसिस माउंटिंग टेस्ट, आपातकालीन गेट इत्यादि पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही बसों में क्षमता के अनुरूप (02 केजी) एबीएस टाइप, ड्राई पाउडर, फायर उपकरण की जांच की जाएगी। अभियान के दौरान यह भी देखा जाएगा कि स्कूल बसों के लिए अधिनियम 125-सी सीएमवीआर 1989 के उपनियम 02 के तहत विशेष मानक निर्धारित किए गए है। उनका पालन किया जा रहा है या नही। इसके अंतर्गत बसों को गोल्डन यलों रंगों में रंगा होना, उसमें स्पष्ट रूप से स्कूल बस लिखा होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपातनिकास, स्टॉप सिग्नल आर्म, हैजर्ड वार्निंग सिस्टम एवं बच्चों की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन भी अनिवार्य है। बसों में स्पीड गवर्नर इलेक्ट्रानिक उपकरण, जो वाहन की अधिकतम गति निर्धारित सीमा से अधिक नही होने देता है, भी लगा होना चाहिए।

स्कूल बसों की अधिकतम गति सामान्यतः 40कि0मी0 प्रतिघंटा निर्धारित है। इसके अलावा बसों में ब्रेक प्रणाली, टायर व सस्पेंशन, लाइटिंग और संकेतक के साथ-साथ वैध दस्तावेजों (आरसी, परमिट बीमा, पीयूसी और वैध फिटनेस) की भी जांच की जाएगी। अभियान में प्रवर्तन दल नियमानुसार बसों के फिटनेस की जांच करेगा। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ चालान, वाहन निरूद्ध, फिटनेस निलंबन इत्यादि की कार्यवाही की जाएगी।

सम्पर्क सूत्र-आशीष सिंह

जिला कारागार में विशेष विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

● जागरूकता शिविर में बंदियों को बताए गए कानूनी अधिकार

निःशुल्क विधिक सहायता, जमानत प्रावधान और न्याय तक समान पहुंच की दी गई जानकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर(ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर आशीष जैन के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला कारागार सीतापुर में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक यादव ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों, शीघ्र न्याय प्राप्ति तथा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आर्थिक या अन्य किसी कारण से कोई भी पात्र व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन सईद अहमद अंसारी, डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम ने किया। वहीं डिप्टी चीफ सुजीत बाजपेई ने बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, जमानत संबंधी प्रावधानों तथा विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। शिविर के दौरान बंदियों की

विधिक जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अशोक कुमार राना, रितिकेश श्रीवास्तव, जिला कारागार के जेल अधीक्षक सहित कारागार का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

01 जुलाई से लागू होगी विकसित भारत-जी राम जी योजना

● ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिन के रोजगार का अवसर, आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण को मिलेगी नई गति

उत्तर प्रदेश में योजना के शुभारंभ की जोरदार तैयारियां- केशव प्रसाद मौर्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी)' ग्रामीण भारत के विकास और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा, उनकी आय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा तथा गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि 01 जुलाई, 2026 से लागू होने वाली इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के सशक्त संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार की गारंटी अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। यह निर्णय ग्रामीण श्रमिकों की आय वृद्धि, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और गांवों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि रोजगार के अतिरिक्त दिनों से ग्रामीण परिवारों की आजीविका मजबूत होगी, स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के

'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मौर्य ने कहा कि वीबी-जी राम जी अभियान ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, पारदर्शी प्रक्रिया और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। योजना के प्रभावी संचालन से गांवों में रोजगार के साथ-साथ विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गांवों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश के ग्रामीण परिवारों की भी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

सम्पर्क सूत्र-बी0एल0यादव

मॉडल संकुल संघ के लेखाकार और एमआईएस सहायक का दस दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

● प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र किये गये वितरित

एस आई आर डी मे विभिन्न विषयो पर विशेषज्ञो द्वारा दिया जा रहा है प्रशिक्षण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब में सरकारी, अर्धसरकारी विभागों, संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अत्यधिक दक्ष और सक्षम बनाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसी कड़ी में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ मे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मॉडल संकुल संघ के लेखाकार एवं एमआईएस सहायक का दस दिवसीय आवासीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन 18 से 27 जून तक आयोजित किया गया यह प्रशिक्षण दीपा रंजन, मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के आदेश पर आयोजित किया गया। संयुक्त मिशन निदेशक प्रवीणानंद ने बताया कि 'मॉडल संकुल संघ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य लेखाकारों और एमआईएस सहायकों को वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन प्रणाली और डेटा प्रबंधन में दक्ष बनाना था, ताकि संकुल स्तरीय संघ पारदर्शिता और व्यावसायिकता के साथ कार्य कर सकें। विश्वास व्यक्त किया कि प्रशिक्षित प्रतिभागी अब समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और मिशन के श्गरीबी मुक्त गाँवश् के लक्ष्य को गति देंगे।' डॉ. नन्दकिशोर साह, मिशन प्रबंधक प्रभारी ने बताया कि प्रशिक्षण में गरीबी के विभिन्न आयामों पर समझ विकसित की गई। 'समूह क्या है, समूह की आवश्यकता क्यों है' और 'प्रभावी समूह के गुण' जैसे विषयों पर खुले सत्र के माध्यम से चर्चा की गई। विजन और मिशन पर चर्चा करते हुए सहभागी विधि से संकुल स्तरीय संघ के सामुदायिक ढांचे को समझाया गया। संगठन और उनके प्रकार पर प्रस्तुति एवं चर्चा के माध्यम से समझ विकसित की गई। प्रशिक्षण में संकुल स्तरीय संघ के तीन स्तंभों - सदस्यता, शासन और परिचालन - की भूमिका तथा जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। मॉडल संकुल स्तरीय संघ के कार्य निष्पादन सूचकांक, दृष्टि पत्र, महत्वपूर्ण हितधारकों की भूमिका, वित्तीय प्रणाली, लेखांकन चक्र, दोहरी लेखा प्रणाली के सिद्धांत, रसीद-वाउचर, खाता बही प्रविष्टि,

प्राप्ति-भुगतान पत्रक, आय-व्यय विवरण, आर्थिक चिट्ठा, वित्तीय प्रबंधन, ऋण प्रबंधन, वित्तीय कार्य निष्पादन सूचकांक, बचत, ऋण, बीमा आदि वित्तीय उत्पादों के महत्व पर गहन अभ्यास कराया गया। आंकड़ों एवं सूचनाओं के महत्व को समझाते हुए प्रतिभागियों से संकुल स्तरीय संघ के लिए योजना प्रपत्र भी भरवाए गए। डॉ सीमा राठौर, प्रशिक्षण प्रसार अधिकारी, डॉ नन्दकिशोर साह रिसोर्स पर्सन ने संयुक्त रूप से प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र विस्तृत किया प्रशिक्षण में मुख्य रूप से जनपद गाजीपुर, कन्नौज, बिजनौर, शामली के प्रतिभागी शामिल हुए। समापन सत्र में राज्य संसाधन व्यक्ति बैजनाथ राम, जिला संसाधन व्यक्ति अमित कुमार सिंह तोमर, मेघा वर्मा, सोनिया, देवेंद्र मिश्रा, कुमारी विमलेश, राजेंद्र सिंह, सूरज सिंह सहित अन्य प्रशिक्षक एवं अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

सम्पर्क सूत्र-बी0एल0यादव

चकबंदी विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रादेशिक बैठक संपन्न

● पदोन्नति, स्थानांतरण, लंबित वेतन और सेवा संबंधी मुद्दों पर शासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में जून प्रादेशिक क्षेत्रीय मिनिस्टिरियल कर्मचारी संघ, चकबंदी विभाग की बैठक शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांधी भवन, कैसरबाग स्थित पुस्तकालय हाल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सक्सेना ने की। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप यादव, संयुक्त मंत्री नवीन प्रकाश पाल एवं राकेश कुमार, संगठन मंत्री नीरज कुमार अरुण, कार्यालय सचिव सरस्वती गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य सुनीता उपाध्याय, राहुल गुप्ता सहित प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी एवं विभिन्न जनपदों के अध्यक्ष और मंत्री उपस्थित रहे। बैठक में वर्ष 2014 की नियमावली के अनुसार जनपदीय कार्यालयों में प्रधान सहायक एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर शासन स्तर से शीघ्र पदोन्नति किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। साथ ही गृह जनपद में तैनाती की नीति लागू करने तथा यदि यह संभव न हो तो कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके गृह मंडल के भीतर किए जाने की मांग की गई। बैठक में जनपद कौशाम्बी के कर्मचारियों का मई माह का लंबित वेतन तथा वर्ष 2025-26 की वार्षिक प्रविष्टि शीघ्र उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, ताकि पदोन्नति एवं एसीपी से संबंधित किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर ऐसा शासनादेश जारी करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत प्रत्येक माह के अंत में संबंधित जनपद के बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी यह प्रमाणित करें कि उनके जनपद में किसी भी कर्मचारी की कोई समस्या लंबित नहीं है। बैठक में जनपद इटावा के कनिष्ठ सहायक प्रमोद कुमार की लंबित समस्याओं के समाधान पर भी सहमति व्यक्त की गई। साथ ही वर्तमान कार्यकारिणी को पूर्व की भांति सक्रिय एवं गतिशील बनाए रखने का संकल्प लिया गया। बैठक के अंत में अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सक्सेना ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह जानकारी संघ के महामंत्री रवि कुमार ने दी।

जमीन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाइ

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गाजियाबाद के बिल्डर संदीप सिंह से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। ईडी अगले सप्ताह आरोपित को पूछताछ के लिए नोटिस भेजेगा। ईडी की लखनऊ जोनल इकाई ने गुरुवार को गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में आरोपित तथा सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़े चार ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी की टीम को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। ईडी की अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि श्रेष्ठ प्रापबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संदीप सिंह भूमि घोटाले के मुख्य लाभार्थी है। आरोपित ने सशस्त्र सीमा बल के सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के सदस्यों को आधी जमीन पर 264 फ्लैट बनाकर देने का वादा किया था। इसके बदले समिति की शेष आधी जमीन के विकास और बिक्री के अधिकार अपने पक्ष में ले लिए थे।

अनियंत्रित होकर पलटा ई-रिक्शा, चालक समेत चार घायल

गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर रोड पर अंबारा पश्चिम मोड़ के पास शनिवार को सवारियों से भरा एक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक समेत चार लोग घायल हो गए। दो घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। डलमऊ थाना क्षेत्र के टप्पा हवेली पूरे बाबा गांव निवासी बृजेश ई-रिक्शा से परिवार की रिंकी, उनकी बेटियां जान्हवी (8) और तान्या (4) तथा बिट्टू देवी के साथ रालपुर में एक रिश्तेदार के यहां धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लौटते समय अंबारा पश्चिम मोड़ के पास ई-रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक बृजेश और रिंकी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों बच्चियों और बिट्टू देवी को मामूली चोटें आईं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बृजेश और रिंकी की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुबना गांव में फलदार पेड़ों पर ठेकेदार द्वारा चलाया गया आरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/ रायबरेलीः महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुबना गांव में फलदार पेड़ों की कथित अवैध कटान का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि, लकड़ी ठेकेदार 'जादूगर' द्वारा आम के हरे एवं सूखे फलदार पेड़ों पर बिना वैध अनुमति आरा चलवाकर शुक्रवार को कटान कराई गई। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि, वन विभागीय सूत्रों के अनुसार, संबंधित पेड़ों की कटान के लिए आवश्यक अनुमति होने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी में बिना वैध स्वीकृति के कटान किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, विभागीय स्तर पर मामले की जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। इस बीच कथित अवैध कटान से जुड़े फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल तस्वीरों के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है और ग्रामीणों ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि, यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे मामलों को बढ़ावा मिलेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि, यदि जांच में अवैध कटान की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले पर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगाहें टिकी हुई हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि, जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुबना गांव में फलदार पेड़ों की कथित अवैध कटान का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आरोप है कि, लकड़ी ठेकेदार 'जादूगर' द्वारा आम के हरे एवं सूखे फलदार पेड़ों पर बिना वैध अनुमति आरा चलवाकर शुक्रवार को कटान कराई गई। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। आपको बता दें कि, वन विभागीय सूत्रों के अनुसार, संबंधित पेड़ों की कटान के लिए आवश्यक अनुमति होने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जाती है।

संक्षिप्त खबरें

वॉर ऑन ड्रग्स' कैंपेन के तहत, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने मिलकर मेडिकल स्टोर चेक किए

फाजिल्का: पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, पंजाब से ड्रग्स को खत्म करने और पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के लिए कमिटेड है और इस लक्ष्य को पाने के लिए, पंजाब में 'वॉर ऑन ड्रग्स' कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन के तहत, आज हेल्थ डिपार्टमेंट, फाजिल्का की बनाई टीम ने सिविल सर्जन डॉ. कविता सिंह और श्री अमित दुग्गल असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आदेशों पर, हरजिंदर सिंह ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के नेतृत्व में और पुलिस डिपार्टमेंट ने गुरसेवक सिंह DSP के आदेशों पर, SHO जुगराज सिंह के नेतृत्व में घुबाया, टाहलीवाला और प्रभात सिंह वाला के 5 मेडिकल स्टोर चेक किए। इस चेकिंग के दौरान, मेडिकल स्टोर में कई तरह की कमियां पाई गई। कई मेडिकल स्टोर का शेड्यूल H-v रजिस्टर मेंटेन नहीं था, कुछ मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे और दूसरी कमियां पाई गईं। इस बारे में ऊपर के अधिकारियों को लेटर लिखा गया है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत सही एक्शन लिया जाएगा। डॉ. कविता सिंह ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने केमिस्ट दुकानदारों से अपील की कि वे दवाइयों की खरीद-बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें, बैन दवाइयां न रखें, फार्मासिस्ट मौजूद रहें और रिकॉर्ड पूरा रखें। इसी तरह आने वाले दिनों में भी इस कैंपेन के तहत चेकिंग जारी रहेगी। इस मौके पर सुखदेव सिंह भी मौजूद थे।

दिल्ली में एक बार फिर दरिंदगी: शाहबाद डेरी में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, सबूत मिटाने के लिए मासूम को नहलाया

दिल्ली। शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय युवक ने पड़ोस में रहने वाली पांच साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपित कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुष्कर्म के बाद उसने सबूत मिटाने के इरादे से मासूम बच्ची को नहला दिया। इतना ही नहीं, किसी को कुछ न बताने के लिए उसने बच्ची को कई थप्पड़ मारे और धमकी भी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता अपने परिवार के साथ शाहबाद डेरी इलाके में किराए के एक मकान में रहती है। उसके माता-पिता पास की ही एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मंगलवार दोपहर को जब बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी उसी इमारत में रहने वाला आरोपित वहां पहुंचा। चूंकि आरोपित का बच्ची के घर आना-जाना था, इसलिए वह उसे पहचानती थी। आरोपी ने बच्ची को बिस्किट दिलाने का झांसा दिया और उसे फुसलाकर अपने कमरे में ले गया, जहां उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद सहमी हुई बच्ची अपने घर लौट आई। रात के समय जब बच्ची असहज महसूस करने लगी और दर्द से रोने लगी, तब उसकी मां उसे तुरंत महर्षि वाल्मीकि अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों द्वारा उपचार और जांच के दौरान इस खौफनाक घटना का खुलासा हुआ। अस्पताल में ही बच्ची ने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में बच्ची का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने पोक्सो अधिनियम और दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को दबोच लिया। आरोपित एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है।

फिर दहल रहा होर्मज; ईरान ने बहरीन पर दागीं मिसाइलें

● ओमान के पास अमेरिका बनाने जा रहा नया समुद्री मार्ग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शनिवार को ईरान ने बहरीन को निशाना बनाकर ड्रोन से हमला किया. इसी दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में एक जहाज पर भी हमला हुआ. माना जा रहा है कि यह अमेरिका की तरफ से रात भर किए गए हवाई हमलों का ईरान की ओर से जवाब था. फारस की खाड़ी में हुए इन हमलों से ईरान के साथ युद्ध के फिर से बेकाबू होने का खतरा पैदा हो गया है, जबकि ईरान और अमेरिका के बीच इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक अंतिम समझौते पर पहुंचने की कोशिश के तहत एक अंतरिम समझौता हो चुका था. यहां तक की कल रात ही अमेरिका-इजरायल-लेबनान के बीच भी एक त्रिपक्षीय समझौता हो गया। अमेरिका ने ये शुक्रवार रात हवाई हमले गुरुवार को जलडमरूमध्य से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में किए थे. यह उन हमलों की कड़ी का हिस्सा था, जिन्होंने युद्ध के दौरान बने नाजुक संघर्ष-विराम को हिलाकर रख दिया है. इस बीच, अमेरिकी नौसेना की देखरेख में काम करने वाले एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने शनिवार को कहा कि वह जलडमरूमध्य में ओमान के पास एक रास्ते का विस्तार करेगा ताकि आने-जाने वाले जहाजों की आवाजाही हो सके. इससे ईरान के साथ तनाव का एक नया केंद्र बनने की संभावना है। ईरान का बहरीन को निशाना बनाना शायद कोई इत्तेफाक नहीं था. यह देश ईरान के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहा है और यहां अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा (फ्लीट) तैनात है. हाल ही में इसने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी की थी. इस बैठक के आखिर में ईरान के हमलों को रोकने और जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) को पूरी तरह खुला रखने की मांग की गई थी. बहरीन के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 'कई ईरानी ड्रोन्स' ने देश को निशाना बनाया. मंत्रालय ने इस हमले को 'नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा' बताया।

इससे पहले शनिवार को ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के जरिए एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया कि उसने 'इस इलाके में अमेरिकी आतंकवादी सेना' के कई ठिकानों को निशाना बनाया है. इसमें यह नहीं बताया गया कि किन इलाकों को निशाना बनाया गया. अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि सेना ने रात भर चले हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया. ईरान के साथ अमेरिकी बातचीत की अगुवाई करने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर कहा कि अगर सीजफायर समझौते को लेकर कोई मतभेद है, तो ईरान को 'फोन उठाना' चाहिए, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान अभी भी समझौते की शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें अहम जलडमरूमध्य (strait) से जहाजों को गुजारने और ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार के भविष्य से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. अंतरिम समझौते के तहत, दोनों पक्षों के पास विवरण तय करने के लिए 60 दिन का समय है. इस बीच, ब्रिटिश सेना के 'यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स' सेंटर ने बताया कि शनिवार को जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में एक टैंकर पर हमला हुआ. सेंटर ने कहा कि क्रू सुरक्षित है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. हमले की जिम्मेदारी तुरंत किसी ने नहीं ली, लेकिन शक फौरन ईरान पर गया. जहाज पर हमले की खबर के ठीक बाद, अमेरिकी नौसेना की देखरेख में चल रहे 'जॉइंट मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर' ने कहा कि ओमान के तट के पास वाले रास्ते का विस्तार किया जा रहा है ताकि आने-जाने वाले ट्रैफिक को जगह मिल सके।

सलमान खान छोड़ेंगे गैलेक्सी अपार्टमेंट?

● गैलेक्सी अपार्टमेंट्स छोड़ेंगे सलमान खान? बांद्रा में समंदर किनारे बनेगा 'भाईजान' का नया 6 मंजिला आशियाना!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सलमान खान का मुंबई वाला गैलेक्सी अपार्टमेंट्स पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां उनके घर पर हमले की खबरें आई तो वहीं किसी के घुसपैठ की जानकारी मिली. लेकिन अब एक खबर आई है, जिसे सुनकर उनके फैंस खुश हो जाएंगे. दरअसल, सलमान खान को नया घर बनाने की मंजूरी मिल गई है, जो उनकी मां सलमा खान के नाम पर है. कहा जा रहा है कि समंदर किनारे जमीन पर 6 मंजिला इमारत बनाने की तैयारी की जाएगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान जल्द ही बांद्रा में अपने परिवार के लिए समंदर किनारे एक नया 6 मंजिला घर बनाने जा रहे हैं. MCZMA ने समंदर किनारे 6 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत दे दी है. महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण MCZMA ने 16 जून को इस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान का नया घर बांद्रा के चिंबई इलाके में बनेगा, जो उनके मौजूदा घर 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' से कुछ ही दूरी पर है. MCZMA के सूत्रों के मुताबिक, यह घर सलमान खान की मां सलमा खान के नाम पर दर्ज प्लॉट पर बनाया जाएगा. यहां पहले 1956 से पूर्व का बना एक दो मंजिला मकान था, जिसे जर्जर हालत के चलते गिरा दिया गया था। जैसा कि सब जानते हैं सलमान खान 1974 से गैलेक्सी अपार्टमेंट में रह रहे हैं. जबकि नई इमारत में ग्राउंड फ्लोर, स्टिल्ट पार्किंग और 6 मंजिलें होंगी. इसका कुल निर्माण क्षेत्र लगभग 1,014 वर्ग मीटर होगा और इसे Sach Developers द्वारा बनाया जाएगा. BMC ने अक्टूबर 2025 में ही इसके लिए प्राथमिक अनुमति IOD जारी कर दी थी. पर्यावरण का ध्यान रखते हुए निर्माण के दौरान एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, आस-पास के इलाके में स्थानीय प्रजातियों के नए पेड़ लगाए जाएंगे। बिश्नोई गैंग के गुर्गों द्वारा गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की गई फायरिंग के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ाकर Y+ कर दी गई है. मुख्य सड़क से दूर एक शांत गली में बनने वाला यह नया घर सलमान और उनके परिवार को पहले से अधिक सुरक्षा और प्राइवेसी प्रदान करेगा।

विजिलेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार को 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चंडीगढ- राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने निखिल गर्ग, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जगराओं, जिला लुधियाना, जो दोराहा ऑफिस का एडिशनल चार्ज भी संभालते हैं, को पटियाला में उनके घर पर 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आज यहां यह जानकारी देते हुए, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त आरोपी ने दोराहा में उसके ट्रांसफर एप्लीकेशन की सिफारिश करने के बदले में उससे 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की रकम लेने के बाद, आरोपी निखिल गर्ग ने शिकायतकर्ता के ट्रांसफर के संबंध में कोऑपरेटिव सोसाइटी दोराहा की प्रोसिडिंग बुक में पिछली तारीख की एंट्री पर साइन कर दिए। इसके अलावा, आरोपी ने सीनियर अधिकारियों के नाम पर रिश्वत की रकम मांगी थी और रिश्वत की रकम मिलने के बाद उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने सीनियर अधिकारी को भी इसकी जानकारी दी थी। शिकायत करने वाले ने रिश्वत की मांग के बारे में पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। रिश्वत देने के लिए तैयार न होने पर, शिकायत करने वाले ने लुधियाना के विजिलेंस ब्यूरो की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) से संपर्क किया। उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया, जिसके दौरान आरोपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दो ऑथराइज्ड गवाहों की मौजूदगी में शिकायत करने वाले से 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास से मौके पर ही रिश्वत के नोट बरामद किए गए। इस संबंध में, आरोपी के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो के EOW पुलिस स्टेशन लुधियाना में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और मामले की आगे की जांच चल रही है।

यमुनापार में बेसहारा गोवंश का आतंक, अवैध डेयरियों पर कार्रवाई की मांग तेज

पूर्वी दिल्ली। यमुनापार की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं। सड़कों पर झुंड बनाकर खड़े गोवंश अचानक हमलावर हो जाते हैं, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन सवार और पैदल यात्री दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बीते बुधवार मंडावली वार्ड की पार्षद शशि चांदना पर अपने कार्यालय जाने के दौरान श्रीराम चौक के पास अचानक एक गोवंश ने हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। फिलहाल उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि ये गोवंश अवैध डेयरी संचालकों के हैं, जिनके खिलाफ शिकायतों के बावजूद नगर निगम कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता। गीता कॉलोनी, मंडावली, आइपी एक्सटेंशन, गणेश नगर और गोकलपुरी की सड़कों पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में बेसहारा गोवंश नजर आते हैं। व्यस्त सड़कों और बाजारों में इनकी मौजूदगी जाम और दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। कई बार ये पैदल यात्रियों पर अचानक हमला भी कर देते हैं। मंडावली निवासी रतन का कहना है कि लगभग हर सड़क पर बेसहारा पशुओं का झुंड खड़ा रहता है, जिसके कारण महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सड़क पर निकलने से घबराते हैं। उनका कहना है कि इलाके में चल रहे अवैध डेयरी कारोबार के कारण सड़कों पर गोवंशों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने पटियाला से 'वॉर ऑन ड्रग्स' कैंपेन के तहत एक अनोखी पहल शुरू की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटियाला- युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए मोटिवेट करने वाले खास फ्लेक्स बोर्ड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के मौके पर, पंजाब सरकार ने 'वॉर ऑन ड्रग्स' कैंपेन के तहत एक बड़ी और अनोखी पहल शुरू की, ताकि राज्य के युवाओं को ड्रग्स की बुराई से दूर रखा जा सके और उन्हें देश सेवा और रोजगार के अच्छे कामों की तरफ मोड़ा जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पटियाला में डिप्टी कमिश्नर पटियाला डॉ. हिमांशु अग्रवाल की अच्छी गाइडेंस में जिला प्रशासन और जिला रोजगार और बिजनेस ब्यूरो, पटियाला द्वारा तैयार किए गए खास जानकारी देने वाले फ्लेक्स बोर्ड ऑफिशियली जारी किए। ये फ्लेक्स बोर्ड जल्द ही पटियाला के 400 खेल के मैदानों में लगाए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इनका फायदा उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ड्रग्स को पूरी तरह खत्म करने के लिए कमिटेड है और ऐसा करने का सबसे असरदार तरीका युवाओं की एनर्जी को सही दिशा देना है। इन खास फ्लेक्स बोर्ड के ज़रिए, यूनिफॉर्म्ड सर्विस में शामिल होने के इच्छुक युवाओं की सुविधा के लिए पंजाब पुलिस, इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए ज़रूरी फिजिकल स्टैंडर्ड और टेस्ट की पूरी जानकारी दिखाई गई है। मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और पटियाला एडमिनिस्ट्रेशन के इस अनोखे कदम की बहुत तारीफ़ की। इस बारे में और जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर पटियाला डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि महाराजा भलिंदर सिंह पोलो ग्राउंड में लगाए गए बोर्ड की तरह, आने वाले दिनों में ये अवेयरनेस फ्लेक्स बोर्ड पटियाला जिले के सभी मेन एथलेटिक ग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड और गांवों के कॉमन प्लेग्राउंड में लगाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण और शहरी इलाकों के युवा इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और ड्रग्स को नकारने और देश की सेवा में अपना कीमती योगदान दे सकें।

मानसून में फलदार वृक्षों की गुठलियाँ लगाएँ

● पर्यावरण की सुरक्षा करें योगेंद्र कुमार सह अधीक्षक तिहाड़ जेल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली: हम सभी जानते हैं कि फल खाने वाले पक्षियों की संख्या दिल्ली में लगातार घटती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण फलदार वृक्षों की लगातार कम होती संख्या है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने मित्रों के साथ वर्ष 2012 में फलदार वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की।हम अपने स्वयं के पैसों से फलदार पौधे खरीदकर लगाते थे। उस समय 3-4 फीट ऊँचे एक स्वस्थ पौधे की कीमत लगभग ?100 से ?150 होती थी, जिससे यह अभियान काफी खर्चीला था।फिर एक दिन मेरे मन में विचार आया कि क्यों न मानसून के दौरान फलों की गुठलियाँ और बीज ही लगाए जाएँ। हमने इस विचार को व्यवहार में उतारा और वर्षा ऋतु में बड़ी संख्या में जामुन, आम, इमली, बेर तथा अन्य फलदार वृक्षों की गुठलियाँ बोई। अगले मानसून तक उनसे लगभग ढाई से तीन फीट ऊँचे स्वस्थ पौधे तैयार हो गए।इसके बाद हमने इन पौधों का निःशुल्क वितरण शुरू किया और स्वयं भी उन्हें उपयुक्त स्थानों पर रोपित किया। आज हमारा पौधारोपण अभियान पूरी तरह निःशुल्क है।मैं आप सभी से भी विनम्र आग्रह करता हूँ कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस मानसून में फलों की गुठलियाँ और बीज अवश्य लगाएँ। अगले वर्ष मानसून में तैयार पौधों को किसी उपयुक्त स्थान पर रोपित करें। बिना किसी बड़े खर्च के हम सभी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।पिछले वर्ष तिहाड़ जेल के बंदियों एवं स्टाफ के सहयोग से हमने बड़ी संख्या में जामुन की गुठलियाँ लगाई थीं, जो आज 2-3 फीट ऊँचे पौधों में विकसित हो चुकी हैं। इस वर्ष मानसून के दौरान दिल्ली सरकार के 'वन महोत्सव' अभियान में हम इन पौधों का निःशुल्क वितरण करेंगे तथा उन्हें उपयुक्त स्थानों पर रोपित भी करेंगे।फलदार वृक्ष लगाने के अनेक लाभ

हैं। ये न केवल पर्यावरण को हरा-भरा बनाते हैं, बल्कि फल खाने वाले सुंदर पक्षियों को भी पुनः उनके प्राकृतिक आवास में लौटने का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही हमें भी बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के ताज़े और पौष्टिक फल प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ये वृक्ष प्रदूषण कम करने, वातावरण को शुद्ध रखने तथा भरपूर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।आइए, इस मानसून एक संकल्प लें—हर घर, हर परिवार और हर नागरिक कम से कम एक फलदार वृक्ष की गुठली अवश्य लगाए। यही छोटा-सा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित, स्वच्छ और समृद्ध पर्यावरण की नींव बनेगा।

बठिंडा पेट्रोल बम हमला केस में बड़ी कामयाबी: जॉइंट पुलिस ऑपरेशन में दो आरोपी गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बठिंडा- बठिंडा में हाल ही में एक क्लिनिक पर हुए पेट्रोल बम हमले में एक अहम कामयाबी मिली है। छद्मत हरजीत सिंह की लीडरशिप में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस टीम के साथ मिलकर इस घटना में कथित तौर पर शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हमले के तुरंत बाद केस दर्ज किया गया और मामले की जांच के लिए बठिंडा पुलिस की कई टीमें बनाई गईं। टीमों ने टेक्निकल सबूतों की जांच करते हुए और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए अलग-अलग सुरागों का पीछा करते हुए गहराई से जांच की। लगातार जांच और इंटेलिजेंस-बेस्ड इनपुट्स पर कार्रवाई करते हुए, बठिंडा पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिससे हमले से जुड़े दो संदिग्धों को पकड़ने में कामयाबी मिली। अधिकारियों ने इस मामले में गिरफ्तारियों को एक बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि यह ऑपरेशन लोगों की सुरक्षा पक्का करने और अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मिलकर की गई कोशिशों को दिखाता है। पुलिस ने कहा है कि घटना के सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ और जांच चल रही है, जिसमें हमले के पीछे का मकसद और दूसरे लोगों का शामिल होना भी शामिल है। जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां और खुलासे हो सकते हैं। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अपना वादा दोहराया और जनता को भरोसा दिलाया कि जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फरीदाबाद में बैनर-पोस्टर लेकर निकले बच्चे, कुत्तों के आतंक से बचाने की मांग की

फरीदाबाद। आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान सेक्टर-70 स्थित मलबरी काउंटी सोसायटी के लोगों ने शनिवार को डाग फीडर्स और बिल्डर के खिलाफ रोष जताया। छोटे-छोटे बच्चे बैनर और पोस्टर लेकर एकसाथ निकले तथा कुत्तों के आतंक से बचाने की मांग की। जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा और नगर निगम से आरडब्ल्यूए व निवासियों की शिकायत के बाद सोसायटी के आठ कुत्तों को उठाया गया है।लोगों ने इन कुत्तों को दोबारा सोसायटी में नहीं छोड़ने की मांग की है। सोसायटी की आरडब्ल्यूए प्रधान डाली उपाध्याय, सचिव नितिन गर्ग, निवासी विमल उपाध्याय और मनीष गुप्ता ने बताया कि कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोसायटी में 32 से अधिक कुत्ते हैं। कुत्तों के हमले के हर महीने दस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को दस वर्षीय पार्थ पर चार-पांच कुत्तों ने हमला दिया था। उसे नीचे दबा लिया और पंजों व दांतों से उसे नोंचना शुरू कर दिया। पार्थ की चीख सुनकर कुछ लोग दौड़कर पहुंचे और काफी मुश्किल से उसे कुत्तों से छुड़ाया था। पार्थ का निजी अस्पताल में इलाज कर रहा है। इससे अन्य बच्चों में भी भय का माहौल है। सोसायटी में बच्चे बैनर और पोस्टर लेकर एकत्रित हुए। जिसपर संदेश लिखा था कि कुत्तों को सोसायटी के बाहर किया जाएगा। जिससे बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल सके। इस दौरान स्थानीय निवासी और आरडब्ल्यूए पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग को मिला जनसमर्थन, श्रीभूमि में 300 से अधिक लोगों ने किए हस्ताक्षर

●स्थायी हाईकोर्ट बेंच के लिए बराक घाटी में तेज हुई मुहिम, श्रीभूमि की जनसभा में उठी न्याय की मजबूत आवाज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि : असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति भवन में एक महत्वपूर्ण जन-जागरूकता सभा आयोजित की गई। रवींद्र सदन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सब्यसाची राय की पहल पर आयोजित इस बैठक में बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की संवैधानिक आवश्यकता, न्याय तक समान पहुंच तथा इस मांग को एक संगठित जनआंदोलन का रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत हाईकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति के महासचिव निखिल पाल के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए डॉ. सब्यसाची राय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बराक घाटी के लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस न्यायसंगत मांग को पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जागरूकता सभाएं जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभा में पूर्व सांसद मिशन रंजन दास, करीमगंज महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य राधिका रंजन चक्रवर्ती, बंग साहित्य एवं संस्कृति सम्मेलन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष सतु राय, सांस्कृतिक हस्ती सुलेखा दत्त चौधरी, प्रोफेसर विश्वतोष चौधरी, शिक्षाविद विभाष देव, महासचिव निखिल पाल, रसराज दास, धर्मानंद देव, अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती, अधिवक्ता तुहिना शर्मा, अधिवक्ता दुर्गा पुरकायस्थ, अधिवक्ता अर्चना दत्त सहित जिले के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और नाट्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि बराक घाटी के लाखों लोगों को न्याय के लिए गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो अत्यंत महंगा, समय लेने वाला और कठिन है। आर्थिक तथा भौगोलिक बाधाओं के कारण अनेक लोग प्रभावी रूप से न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना समय की मांग है और यह संविधान में निहित समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई क्षेत्रीय या राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक न्याय के अधिकार को सुनिश्चित करने की एक उचित मांग है। इस मांग को बराक घाटी के सभी वर्गों का व्यापक समर्थन प्राप्त है और सरकार तथा संबंधित अधिकारियों से इस दिशा में शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की अपील की गई।

सभा के अंत में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की स्थापना के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 300 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया। यह इस मांग के प्रति जनता के व्यापक समर्थन का प्रमाण माना गया। बैठक में सर्वसम्मति से बराक घाटी में शीघ्र स्थायी हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग दोहराई गई तथा समाज के सभी वर्गों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस जनआंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया गया।

स्थानीय लोगों ने विकास में जनभागीदारी बढ़ाने की अपील

● समाजसेवी पूजा ढौडियाल शर्मा ने उठाए सवाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। आया नगर में विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। समाजसेवी पूजा ढौडियाल शर्मा ने क्षेत्र में सड़कों और नालियों के निर्माण कार्यों पर हो रहे खर्च को लेकर पारदर्शिता की आवश्यकता जताते हुए नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। पूजा ढौडियाल शर्मा ने कहा कि आया नगर में सड़कों और नालियों पर बड़े पैमाने पर धन खर्च होने की बात कही जाती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ वास्तव में लोगों को जमीन पर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि इसका आकलन क्षेत्र की जनता स्वयं कर सकती है। उन्होंने बताया कि आया नगर के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर उनकी ओर से संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं, ताकि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान कराया जा सके।समाजसेवी पूजा ढौडियाल शर्मा ने कहा कि केवल सोशल मीडिया या व्हाट्सएप समूहों में चर्चा करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे छुट्टी के दिनों में छोटी-छोटी बैठकों के माध्यम से अपने सुझाव साझा करें और क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक रूप से आगे आएं। उनका कहना है कि लोगों के सुझावों को संकलित कर संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा, जिससे जनहित के कार्यों को गति मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि आज की व्यस्त जीवनशैली में सभी लोग अपने-अपने कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन अपने मोहल्ले, गलियों और समाज की देखभाल करना भी प्रत्येक नागरिक की

जिम्मेदारी है। यदि हर नागरिक थोड़ी-सी भागीदारी निभाए, तो क्षेत्र के विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जा सकती हैं। गौरतलब है कि समाजसेवी पूजा ढौडियाल शर्मा लंबे समय से आया नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं, महिलाओं के मुद्दों, स्वच्छता, सड़क, नाली, पेयजल तथा अन्य जनसमस्याओं को लेकर सक्रिय रूप से आवाज उठाती रही हैं। वे समय-समय पर स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित कर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रयासरत रहती हैं।